



न्यायालय नामान गृहका महोदय, राजस्व पंडित व्यालियर के म, सोपाव

PBR | फूलारा०८ | श्रीपाल | श्रृंखला | २०१७ | ४९४४

ଶ୍ରୀମତୀ ପିଲାତ୍କାରୀ
ଗୁଣ୍ଡାରୀ ମହିଳା କମିଟି
୨୯-୧୧୮-୦୧
ମୁଦ୍ରଣ ପରିଷଦ
B
୨୯-୧୧୮

महेश बाबूराव के ₹३० लाई कंजीलाल क्षमाराव

मेहरा कामटा एवं ₹१० थो कंजोलाल कुमारटा

१०८ अस्ति विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु

आयु वयस्ति, निवासा ग्रन्थ विषयः ।

તાંડુલા જિલ્લા મોપાલ

पुनरोद्धार क्रमांक-

-पनरोद्धकता।

四

- १- भारतसंघ पुनर रव० औ मुंगाराम, ग्राम्य-वयस्क
 २- वंदनसंघ पुनर रव० औ मुंगाराम ग्राम्य-वयस्क
 दोनों निवासोमण ग्राम प्रपलिया बाज छौं
 तहसील हजूर जिला बोपाट

पश्चाद्याम आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-५० म.प्र. क्र. रा. संहिता । १९५९

पुकारण क्रमांक 135/3F 12/16-17

मार्गदर्शक दिनांक:- 05-05-2017

ग्राहितस्य न्यायालय :- राजस्व निरादेक तदत्ताल हुङ्गर मृत्यु 2, भोपाल

पुनरोक्षणकर्ता के विवाहित्व को भूमि खारा नमांक 132/1, 133/1, 134/1,
एकबा 0.95 हेक्टर ग्राम पिपलिया बाज छाँ तड़तों न हूँगर जिना ओपाल
स्थित होकर उन विद्वगण को भूमि खारा नमांक 135, 136, एकबा समय
0.71 हेक्टर हो लगी हुँ भूमि है। उन विद्वगण ने उक्त भूमि का सामांक
हेतु अविद्वन पत्र प्रत्युत किया जिसे अधिस्थव न्यायालय रिआउपरौपत्र प्रेस
नमांक के रूप में रिंडित कर सामांक लो कार्यविधी प्रारंभ का बोकर अंतिम
लिख से नदा को गया जिससे पुनरोक्षणकर्ता द्विःहित होकर उपरौपत्र अधिस्थव
न्यायालयके प्रकरण के विन्द्र मान्य न्यायालयके समका निम्न प्रकरण के रूपों
एवं ग्रामारो पर यह पुनराक्षण प्रत्युत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी / भोपाल / भू.रा. / 2017 / 4944

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारी एवं अभिभावकों
आदि के हस्ताक्षर

30-1-2018

आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं कर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि से छूट हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 48 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की ग्राह्यता के संबंध में निगरानी मेमों का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से यह निगरानी सीमांकन कार्यवाही के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानी मेमों में उठाये गये आधार प्रकरण के ग्राह्यता के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

अध्यक्ष